ally the listed medicines arc available in the Ayurvedic dispensaries/units. However, if any medicine is not available in the dispensary the same is made available through the local chemist by the Inchargc of the dispensaries/Units. The need for courtsey has been cmplcasizcd to the dispensary staff.

(c) and (d) The dispensaries/hospitals/units submit regular monthly indent of medicines as per requirement to the Midical Store Depot which supplies the medicine within four-five days. For this purpose a scheduled programme for submission of regular indents is circulated to all the dispensarics/hospitals/units well in advance.

लघु उद्योगों को दी गयी रियायतों का प्रभाव

382. **श्री रामजी लाल**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति का पालन करते हुए लघु उद्योगों को दी गई रियायतों से उन्हें वर्ष 1991 से हुए फायदे/नुकसान का ब्यौरा क्या हैं;और

(ख) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया हैं तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.अरूणाचलम): (क) सरकार की उदार नीति के तहत 1991 से लघु उद्योगों को छूट आदि के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं:-

(1) लघु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी मानदण्ड को समाप्त किया गया हैं।

(2) भूमि तथा भवन को छोड़कर,5 लाख रूपये तक की स्थायी परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश वाले लघु उद्योग सेवा व व्यावसायिक उद्यमों से संबंधित उद्योगों को लघु उद्योग के बराबर का दर्जा दिया गया हैं।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिबंधित सूची को समाप्त किया गया हैं।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जल तथा वायु-प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अनुमति लेने की कार्यपद्वति को सरल बनाया गया हैं अब लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक रसीद (एक्रोलेमेंट) प्राप्त करनी होती हैं जिसे स्वीकृति के रूप में माना जाता हैं,लेकिन इसमें 17अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

5. लघु औद्योगिक इकाइयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक इक्विटी भागीदारी करने की अनुमति दी गई हैं।

6. लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को निलंबित भुगतानों पर ब्याज से संबंधित एक अधिनियम की घोषणा अप्रैल,1993 में की गई।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के अनंतिम तथा स्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई हैं।

8. लघु आद्योगिक इकाइयों के हित में कोई उत्पाद-शुल्क कार्य पद्वतियों को सरल बनाया गया हैं। लघु उद्योग उत्पादन शुल्क छूट योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब उद्योग निदेशालय में पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। लघु औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड उत्पादन शुल्क प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे और लघु औद्योगिक इकाइयों को और कोई अतिरिक्त रिकार्ड नहीं रखना हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी हैं। केवल तिमाही विवरणी ही पर्याप्त हैं। यदि वस्तुओं की बिक्री 30 लाख रूपये के अंदर हो तो केन्द्रीय आबकारी विभाग में कोई घोषणापत्र दायर नहीं करना हैं। छूटों से कोई हानि होने की रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं।

Repeated incidents of food Poisoning

383. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that repeated incidents of food poisoning are occurring in Delhi due to the non implementation of licencing rules under Rule 49 and 50 PFA AcfRules 1954 since the last Eighteen years thereby causing great loss to public health and also huge loss of Government revenue;

(b) if so, whether it is also a fact that the Central Government has issued repeated instructions/directions to the authorities of Delhi to implement the provisions of licencing rules in the interest of public health;

(c) if so, the action proposed by Government to take further steps under Section 22(A) of PFA ActRules in view of (a) and (b) above; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A. R. ANTULAY): (a) As per information recicved from the Govt, of National Capital Tcrriotry of Delhi, some cases of food poisoning have been reported in Delhi in the past. However, the same cannot be attrtibutcd to non-implementation of licensing rules.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) In view of a policy decision taken by the Government of National Capital Territory of Delhi to implement licensing rules, no directions under Section 22-A of PFA Act, 1954 are rcquried to be issued. Action has been separately initiated by the Govt, of National Capital Tcrritorry of Delhi to creat additional posts for the implementation of licensing rules.

Non-acceptance of Indian currency by duty free shops in Air India's international flights

384. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only dollars arc accepted by duty free shops in the international flights of Air India; and

(b) if so, the reasons for not accepting Indian currency during such flights?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) No, Sir. Besides the US Dollar, 20 other international currencies are accepted for duty free sales on board Air India flights. However, due to restriction imposed by the Reserve Bank of India, Indian rupee is not accepted for duty free sales.

मौलिक सुविधाओं के अभाव में डी.डी.ए.के .खाली पड़े फ़्लैट

384. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** :

श्री राजनाथ सिंह:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलिक सुविधाओं के अभाव में डी.डी.ए.के कितने फ्लैट गत वर्ष के दौरान खाली पड़े हैं;

(ख) खाली पड़े डी.ड.ए.के फ्लैट किन-किन वर्गो/टाइपों के हैं और वे कहां-कहां हैं और कब से खाली पड़े हैं;

(ग) इन खाली पड़े फ्लैट के परिणामस्वरूप डी.डी.ए.को कितना वित्तीय घाटा हुआ हैं;और

(घ) सरकार इन फ्लैटों में कब तक मौलिक सुविधायें प्रदान कर देंगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया हैं कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 21,511 फ्लैट खाली पड़े हैं। इन फ्लैटों को श्रेणी-वार ब्यौरा,उनकी स्थिति खाली रहने की अवधि सहित अनुलग्रक में हैं। [**देखिये परिशिष्ट** 176, **अनुपत्र सं**,16]